RAJYA SABHA

Monday, the 5th May, 1997/
15 Vaisakha, 1918 (Saka)

The House met at eleven of the clock

Mr. Chairman in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Say of MPs' in Central Schemes

401. SHRIMATI ANADIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned 'UF wants MPs to have more say in Central Schemes' which appeared in the 'Times of India' dated the 28th February, 1997; and

(b) if so, the details of the schemes proposed to be brought under the programme apart from MPLADS?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (b) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. Members of Parliament (MPs) are already associated with the implementation of Centrally Sponsored Schemes (CSS) of poverty alleviation like Integrated Rural Development Programme (IRDP), Jawahar Rozgar Yojana (JRY), and Employment Assurance Scheme (EAS).

MPs are members of the District Rural Development Agency (DRDA) Governing Body which provide guidance and direction to the DRDAS in the implementation of rural development programmes. All schemes/ projects are approved by the Governing Body of the DRDA. MPs participating in the meeting of the DRDAs are apprised regarding the criteria of selection of beneficiaries and projects as laid down in the schematic guidelines and their views in this regard are discussed.

The State Governments have been instructed to constitute District and Block Level Vigilance and Monitoring Committees with MPs representing their respective districts on them. These Committees supervise exercise vigilance, and monitor the implementation of all programmes of the Ministry of Rural Areas & Employment.

The MPs are also members of the District and Block Level EAS Committees which supervise the implementation of the EAS and may suggest from time to time to the State Government such steps as in their opinion are necessary for more effective implementation of the scheme.

As per the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 the 29 subjects identified in the Eleventh Schedule would be transferred to Panchayati Raj Institutions (PRIs) with a corresponding transfer of power and funds. Poverty alleviation is one of the 29 subjects included in the Eleventh Schedule. The Approach Paper to the Ninth Five Year Plan has adopted democratic decentralisation as in integral part of the planning process, with the responsibility vested in PRIs for preparing plans for economic development and social justice and implementing them. MPs are represented on various district/block level Committees which ensures their involvement in the overall implementation and supervision of poverty alleviation programmes.

श्रीमती आनन्दी ज॰ पटेल: सभापति महोदय, मेरा पहला प्रश्न है, सांसद् डी.आर.डी.ए. के सदस्य हैं और अन्य जिला तथा ब्लाक स्तरीय तथा मानिटरिंग समितियों के सदस्य हैं। यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों और रोज़गार मंत्रालयों के सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का निरीक्षण, सतर्कता एवं मानिटरिंग का कार्य करती है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कार्य के करने के लिए सांसदों को राज्य सरकारों की ओर से कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है? बिना साधन एम॰पी॰ वहां कैसे जाएगा और कैसे निरीक्षण करेगा? यदि कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो केन्द्र सरकार सांसदों को सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है? यदि कोई सुविधा नहीं है तो सांसदों की समिति के सदस्य बनाए जाने से कोई फायदा नहीं होगा।

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Mr. Chairman, Sir, if there are any particular facilities that the Member is interested in, for

example, information or the structure of schemes at the district or block-level, I will be very happy to look into.

SHRI S.B. CHAVAN: It is totally a different question.

MR. CHAIRMAN: What facilities did the Member want? There are all manner of facilities.

श्रीमती आनन्दी ज० पटेल: यदि कोई कार्य चल रहा है ब्लाक स्तर पर या जिला स्तर पर तो वहां जाने के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए एम०पी० को ट्रांसपोर्ट आदि का कोई साधन तो चाहिए? वे वहां कैसे जायेंगे, क्या वे वहां पैदल जायेंगे? एक ब्लाक में कई कार्यक्रम चलते हैं तो वहां जाने के लिए व्हिकल तो चाहिए?

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Mr. Chairman, Sir, normally we have travel assistance and so on for attending official meetings but if there is anything any particular Member has in mind, if he or she brings it to my attention, I will look into it. Our intention is that Members of Parliament should be effective Members in this consultation process that we have set up for them at the level of DRDA and other bodies.

MR. CHAIRMAN: Have your second supplementary, please. (*Interruptions*)

श्री संजय निरूपम: मंत्री जी का जवाब संतोषजनक नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Please, I have not called you.

श्रीमती आनन्दी ज० पटेल: आपने इसमें जवाब दिया है कि राज्य सरकारों ने जिला और ब्लाक स्तरीय सतर्कता तथा मॉनिटरिंग समिति का गठन किया है जिसका संबंधित जिला के सांसद् प्रतिनिधित्व करते हैं। यह समिति ग्रामीण क्षेत्र और रोज़गार मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण, सतर्कता एवं मॉनिटरिंग का कार्य करती है तथा इसमें प्रतिनिधित्व जब एम०पी० करते हैं तो वहां जाकर वह कैसे मानिटरिंग करेगा क्योंकि वहां जाने के लिए कोई व्हिकल आदि की सुविधा तो है ही नहीं, बिना कोई सुविधा वह मॉनिटरिंग करेगा? आपने इसमें लिखा है (**व्यवधान**)

श्री योगेन्द्र के० अलघ: माननीय सदस्या जानती हैं कि हमें ट्रेवलिंग एलाउंसेज मिलते हैं और जो भी सुविधाएं हमारी हैं (**व्यवधान**)

श्रीमती आनन्दी ज० पटेल: वह तो कमेटी के लिए हैं। ...(**व्यवधान**) वह तो पार्लियामेंट्री कमेटी में जब हम आते हैं तब हमको मिलता है। (**व्यवधान**) जिला स्तर पर,ब्लाक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नहीं मिलता।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: कुछ राज्यों ने इस प्रकार का प्रावधान किया है कि वे एम०पीज़ को कुछ सुविधा देते हैं। मैं समझता हूं कि गुजरात में उस तरह की सुविधा नहीं है उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिलाधीशों को यह आदेश दिए हैं कि 2, 3 या 5 रोज के लिए उन को एक व्हीकल मिलनी चाहिए जिस से कि वह अपने लोकल डवलपमेंट वर्क्स को देख सकें। उस तरह की सुविधा यदि गुजरात में नहीं है, तो वह दी जानी चाहिए क्योंकि यह सही है कि आप ने कार्य की देखभाल के लिए अगर उन को आदेश दिया है और उन से यह अपेक्षा की जाती है तो मैं यह भी आशा करता हूं कि उस के लिए प्रबंध किया जाए।

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*).... The Minister has to answer this. ... (*Interruptions*)... Do you want to answer this? ....(*Interruptions*)... This is a very wide demand. ...(*Interruptions*)...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: This is a specific demand. वह तो गुजरात से ही आते हैं, इसलिए जल्दी करवा देंगे।...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Let the Minister answer. ...(*Interruptions*)...

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Sir, regarding MPLADS which is a separate area, we have told the Collectors that they should give priority, subject to their other work, to accompany the MPs if they would like to go to their works. With regard to general instructions, I would like to say that the Government of India is very keen that the MPs participate in this activity and for this purpose facilities should be provided to them. I will be very happy to send general instructions to the States. But keeping in view the fact that the State Governments have their own resource constraints, their own traditions and so on, I do not think that it would be proper for me to interfere in their functioning beyond this.

श्री संजय निरूपम: धन्यवाद सभापति महोदय, मैं एम०पी०एल०ए०डी० स्कीम के तहत ही बात करना चाहता हूं।

श्रीमती आनन्दी ज० पटेल: सभापति जी, मेरा सैकंड सप्लीमेंटरी बाकी है।

MR. CHAIRMAN: I thought you had put your second supplementary. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती आनन्दी ज० पटेल: अभी एक ही हुआ है, वह तो क्लेरीफिक्रेशन था। महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी के पास विकास कार्यों में डी०आर०डी०ए० ब्लॉक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत आई है? यदि शिकायत आई है तो केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है? महोदय, राज्य सरकार तो कार्यवाही नहीं करती है तो क्या केन्द्र सरकार ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही करना चाहती है और यदि नहीं तो इस का क्या कारण है?

श्री योगेन्द्र के० अलघ: सर, अगर कोई भी स्पेसिफिक शिकायत हमारे पास आती है तो हम उस को राज्य सरकारों के साथ जरूर लेते हैं फिर चाहे वह एम०पी०एल०ए०डी० में हो या कोई दूसरे प्रोग्राम में हो।

श्री संजय निरूपम: सर, मैं मुंबई में रहता हूं और मैंने एम०पी०एल०ए०डी० स्कीम के तहत जो हमारा फंड है, उस के इस्तेमाल के लिए नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑप्ट किया है। अब नागपुर डिस्ट्रिक्ट मुंबई से कितनी दूर है, यह हम सभी जानते हैं। इस कार्य की देखरेख के लिए मुझे अक्सर मुंबई से नागपुर आना-जाना पड़ता है। अब इस की कोई व्यवस्था नहीं है कि वह खर्च कौन वहन करेगा? इस बार मैं नागपुर गया तो मैंने देखा कि वहां 3, साढ़े 3 महीने से 1 करोड़ रुपया अकाउंट में जमा है। उस एक करोड़ रुपए पर साढ़े 3 लाख के आसपास इंटरेस्ट जमा हो गया है। मैंने पूछा कि इस इंटरेस्ट का इस्तेमाल कौन करेगा, इसका उपभोग कौन करेगा? उनके पास इस का कोई जवाब नहीं है। फिर मैंने सरदार पटेल भवन में जो वहां के आफिस इंचार्ज हैं, उन से पूछा कि हमारे फंड की जो इंटरेस्ट की रकम आती है, उस रकम का इस्तेमाल कौन करेगा? तो मेरा सवाल यह है कि उस इंटरेस्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं हम अपने विकास कार्यों पर करें या फिर हमें जो टी०ए०/डी०ए० दिया जाता है, क्यों नहीं उस रकम में से टी०ए०/डी०ए० वगैरा का प्रोवीजन किया जाए?

श्री योगेन्द्र के० अलघ: सर, वैसे यह सवाल एम०पी०एल०ए०डी० पर नहीं है, फिर भी जहां तक ब्याज का सवाल है, वह सवाल हमारे मंत्रालय ने भारत सरकार में उठाया है और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में उस ब्याज का किस प्रकार से उपयोग हो, उस के संबंध में हम माननीय सदस्यों को सरकार का निश्चय बता सकेंगे।

श्री संजय निरूपम: सर, यह सवाल कई सालों से अटका पड़ा है।

श्री योगेन्द्र के० अलघ: सर, गाइडलाइंस में उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ब्याज का सवाल अभी 3-4 महीने पहले लिया गया है और उस को हम वित्त मंत्रालय के साथ ले रहे हैं। हमारी तरफ से यह प्रयत्न है कि ब्याज के पैसों से संसद सदस्यों के लिए और कुछ स्कीम्स चलाने के तरीकों के लिए भी कुछ साधन मिलें, लेकिन जब तक सरकार यह निश्चय नहीं लेती, इसके बारे में से कोई फर्म अनाउंसमेंट अभी नहीं करना चाहता। लेकिन हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि इस स्कीम को चलाने में मदद कर सकें।

आपका मुम्बई से नागपुर जाने का जो सवाल है, वह तो जैसे मैं एम०पी० हूं, माननीय सदस्य भी एम०पी० हैं, हमारे पास रेलवे पास हैं और फैसिलिटी है, वहां तो हम जा ही पाएंगे लेकिन जिले में जाने की जो सुविधा है, उसके बारे में हम कुछ प्रयत्न करेंगे।

श्री संजय निरूपम: लेकिन कब तक यह डिसीज़न हो जाएगा, कुछ समय बता सकें तो बता दीजिए आप?

MR. CHAIRMAN: Mr. Surjewala.

श्री संजय निरूपम: सर, मैं जानना चाहता हूं कि कब तक यह फैसला हो जाएगा?

MR. CHAIRMAN: Please, sit down. ...*(Interruptions)*... Please, sit down.

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इन्होंने अपने जवाब के पैरा नम्बर 3, 4 और 5 में विभिन्न बातें लिखी हैं कि जो पार्लियामेंट के मैम्बर है उनको किस तरह से सरकार के कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। पैरा नम्बर 3 में इन्होंने लिखा है कि "ब्लॉक और जिला स्तर पर विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई गई हैं, जिनके अंदर एम०पीज़० मैम्बर हैं और ये कमेटियां सुपरवाइज़ करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं अपनी विजिलेंस को और मॉनिटरिंग करती हैं इम्प्लीमेंटेशन को" नैक्सट पैरा में इन्होंने लिखा है कि "एक और कमेटी है, ई०ए०एस० कमेटी है, जिला और ब्लॉक लेबल पर, उसके भी मैम्बर हैं मैम्बर आफ पार्लियामेंट" नैक्सट पैरा में इन्होंने लिखा है "कि 29 ऐसे विषय हैं जो ट्रांसफर कर दिए गए हैं पंचायती राज की और जो हमारे मैम्बर हैं, यह जिला परिषद और पंचायत समिति के मैम्बर हैं।"

मंत्री महोदय, मैं आप से कहना चाहता हूं कि हम लोग गांवों में रहते हैं, दिल्ली में तो इन बातों का पता लगता नहीं है, मैं आपको कह सकता हूं कि जो कमेटियां

आपने लिखी हैं, इस तरह की कोई कमेटी नहीं बनी हुई हैं। यह कमेटियां केवल आपके कागज़ों में हैं और कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई विजिलेंस नहीं है। आज तक हमको कोई चिट्ठी नहीं आई, किसी मीटिंग में बुलाया नहीं गया। यहां तक कि पंचायती राज, जिसका इतना ढिंढोरा पीटा गया है और आप पीट रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं 1961 और 1964 में दो बार पंचायत समिति का इलेक्टिव मैम्बर था, जो उस वक्त अधिकार थे, सभापति जी, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतों को कोई अधिकार नहीं हैं, पूर्ण रूप से उनकी जान अधिकारियों के हाथ में है और ब्लॉक और जिला स्तर के या छोटे स्तर के जो अफसर हैं, वे उनके खिलाफ मुकदमे करते हैं। कोई उनको अधिकार नहीं है, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। आप मैम्बरों को अगर फैसिलिटी देना चाहते हैं तो हम केवल ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहते हैं। हम कोई अलहदा गाड़ियां नहीं चाहते हैं। आपके जिलों में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के पास बेशुमार गाड़ियां हैं, आप उनको कहें कि जब कोई मैम्बर आफ पार्लियामेंट कोई प्रोग्राम बनाकर दें तो आप उनको जीप या गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए देंगे, उनके साथ जाएंगे। आप यह कर सकते हैं अब सरकार सोचेगी, सरकार सोचेगी, सरकार कभी नहीं सोचेगी। क्या आप इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे, जो मुद्दे मैंने उठाएं हैं?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Mr. Chairman, Sir, it is a fact that we were never involved in nor were called to any of these meetings. It is true that the constitution of such committees is totally fictitious. Or, if they are existing, it is only on paper.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Mr. Chairman, Sir, ours is a big country. The situation varies across different States. These instructions have been sent by the Department of Rural Development a few months ago. For example, nine States, including my own, have set up such committees. It just happens that of the States about which the two hon. Members spoke, one State has not set it up and the other States has informed us that it is in the process of setting it up. ..(*Interruptions*) ... Andhra has really made very genuine efforts in decentralisation. When they say that they are planning to set up these committees or are in the process of setting them up, I am sure, bold action will be taken. I think, the hon. Members point out that all the States have not given the panchayats the powers that they should have under the Constitutional Amendment जोकि इस सदन से भी पास हुई हैं, लोक सभा से भी पास हुई है कि कुछ राज्यों में अभी तक वह लेजिस्लेशन या उसके रूल्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि माननीय सदस्य मेरे साथ होंगे, जब हम यह कहते हैं कि हम यह चाहते हैं कि ग्राम सभा के स्तर पर इन स्कीम्स के बेनिफिशरीज़ चुने जाएं तो वह एक बड़े महत्व की बात है। और जहां वह नहीं हो रही है, वहां मेरा बड़ा नम्र निवेदन होगा माननीय सदस्य और सदन से, कि हम अपनी तरफसे कोशिश करें। यह स्कीम में जो ट्रांसपेरेन्सी है, वह तभी आएगी, जैसा योजना आयोग ने और कितनी ही कमेटियों ने, जिन्होंने इस बात का अध्ययन किया है, कहा है। तो ग्राम-सभा के स्तर पर हमको इनको स्ट्रेन्थन करना पड़ेगा और तब यह जो बेनेफिशरीज हैं उस स्तर पर चुने जाएं, जिनको यह फायदा इन स्कीम का मिलेगा। जिला स्तर पर जो समितियां हैं, वहां मेरा निवेदन होगा माननीय सदस्यों से, कि हम अपनी तरफसे पूरा प्रयत्न करें। वैसे मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं कोई शहर के विस्तार से नहीं आता, मेरा घर तो अहमदाबाद के एक ग्रामीण एरिए में है।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: सभापति जी, मैं केवल यह कहना चाहूंगा, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वह यह कि औरतें जो 33 परसेंट सरपंच बनी थीं, उनमें से अधिकतर आज मुअत्तल कर दी गई हैं और किसी भी लेडी को कोई चार्ज या कोई काम नहीं दिलवाया गया है। इतनी डिसक्रिमिनेशन है। इसी प्रकार जो हरिजन, बैकवर्ड और गरीब सरपंच थे, वे भी अधिकतर मुअत्तल कर दिए गए हैं। आप खुद मोनीटर नहीं कर सकते, हम क्या मोनीटर करेंगे। आप मंत्री होकर भी मोनीटर नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे।

MR. CHAIRMAN: This is a different question.

SHRI S.B. CHAVAN: Mr. Chairman, Sir, there are two questions on which I would like the hon'ble Minister to react. First, I am sure the hon'ble Minister must be aware of the fact that after the Constitutional Amendment, we thought that the Panchayati Raj institutions were going to get more powers and that the money would be sent to them directly. The hon'ble Minister must be aware of the amendment that the Maharashtra Government has brought out. All these institutions like the Zila Parishad and other sub-committees are

having the term of chairmanship just for one year. If one year is going to be the term, it means that all these Panchayati Raj institutions are only in name and they do not want that things should be implemented through the Panchayati Raj Samiti.

The second point on which I would like to solicit information from the hon'ble Minister is that there are a large number of schemes for which the Central Government has been sending money directly to the State Governments so that the schemes could be properly implemented. But our experience has been that these funds are being totally misutilized. They are diverted for different purposes altogether. Even for payment of salaries this amount has been used and I have been getting a stock reply, "This is a matter of the State Government, we can't interfere in the matter." If the position is like that, then the question of monitoring to be done by the hon. Members of Parliament becomes a nominal thing, in which we are not going to get any response from the Government of India. So, my request would be even if it means the changing of certain provisions of the Act, we have to change them. But, in order to see that the schemes are properly implemented, some kind of conveyance facility will have to be provided to the Members so that we can see things for ourselves and thereafter, approach the officials and see to it that things are properly implemented. What are you going to do in the matter? But, if you are just going to go by the standard procedure saying, "No, we can't possibly do it", things will not improve. State Governments have been doing everything for their Members, but when it comes to Members of Parliament, we find that our approach is very conservative in this matter. I would request the Hon'ble Minister to please react on both the issues.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Sir, I am very grateful to Chavan Sahib for raising this very serious issue. Now, the Planning Commission is very much bothered about the kind of questions that the hon. Member has raised. The situation at present, very briefly speaking, is that the Constitutional Amendments have been passed.

Most of the States have passed the concerned legislation. Almost all of them have also notified the rules. But in some cases, as the hon. Member has said, these kinds of problems have come up in the review undertaken by the Department of Rural Development and in the study that the Planning Commission had got done under the supervision of Shri D. Bandhopadhyay. Shri L.C. Jain and I was also on this committee. This was done when I was outside the Government. After a detailed review of the States, we have brought this out.

The Department of Rural Development and the Planning Commission constantly bring it to the attention of the State Governments. The intention of the Government is that not only these functions must go to the lower level, but the requisite funds and authority must also go to the lower level.

I would be very happy to pass on to you this review report. This runs into hundreds of pages. The details have been brought out in this report. Here, we are talking about a very basic issue, i.e. the functioning of the system in the whole country. I would again appeal to the hon. Members. We would be very happy to share this review report with you. But we will keep on making efforts. Some States have done well. Others are beginning. The situation really varies across the States.

Now, as far as the question of transport is concerned, my Department's view is this. If we are able to make use of the funds under MPLADS-the hon. Member had raised this question-we will be able to provide some more transport facilities to the hon. Members. But this is something on which I cannot give an assurance right now because Government is yet to take a view on this. However, we will be very happy to bring it to the attention of the States that when hon. Members are members of these important committees, these facilities must be made available to them.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Sir, it is a question of developing more areas. Take, for example, the Vidarbha region. It is the policy of the Government of India. Sometime back, the Government of India declared the 'no industry districts'. In

Maharashtra, particularly, in Vidarbha, only one district has been declared, i.e. Gadchiroli.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: That is the next question.

MR. CHAIRMAN: Dr. Karan Singh.

DR. KARAN SINGH: Sir, I did not want to put any question.

I did not raise my hand on this question.

Expansion of SSIs in Vidarbha Region of Maharashtra

*402. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps for the expansion of Small Scale Industries in the Vidarbha region of Maharashtra;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Small Scale Industries Corporation is supplying machinery to the entrepreneurs on hire purchase basis;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether Government have noticed any increase in the number of Small Scale Industries in the Vidarbha region; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (f) A statement is laid on the Table of the House.

(a) and (b) Yes, Sir. The Central Government sets out the policy framework for promotion and development of small scale industries. It also renders certain support services by way of consultancy, technical services, creation of infrastructure, training and entrepreneurship development etc. Small Industries Service Institute, Nagpur (a field office of the Small Industry Development Organisation) provides training, technical consultancy and other services to the existing and prospective entrepreneurs in the region. Assistance has been provided for setting up a sub-Contracting Exchange through Non-Governmental Organisation in Vidarbha region. One Integrated Infrastructure Development Centre was sanctioned by the Government in September, 1994 in Yeotmal district under the scheme of IID. The Government of Maharashtra is providing incentives by way of Sales Tax exemption, refund of octroi/entry tax, refund of electricity duty, concession in capital cost of power supply and contribution towards feasibility studies. Through National Small Industries Corporation (NSIC) export of Rs. 1 crore was made from Vidarbha region for 'cable and conductors' to Nigeria during 1996-97. NSIC also provided raw-material assistance of Rs. 58 crores in Vidarbha región during the last three years. The NSIC has established a sub-office in Nagpur in 1996. The Small Industries Development Bank of India has sanctioned and disbursed cumulative assistance to the tune of Rs. 204.4 crores and Rs. 149.9 crores respectively in the Vidarbha region to 5715 units during the period 1990-97.

(c) and (d) The National Small Industries Corporation provides machinery on hire purchase, equipments on lease, marketing assistance etc. to small scale units. So far a total of 28,275 SSI units have been assisted under hire purchase by the NSIC in the country.

(e) and (f) yes, Sir. The cumulative number of SSI units registered in the Vidarbha region for the years 1993, 1994, 1995 and 1996 (provisional) are 9244, 10586, 12549 and 14346 respectively.

MISS SAROJ KHAPARADE: Sir, a very lengthy statement has been given by the hon. Minister. However, there are a few questions which I would like to put to the hon. Minister.

I am sure the hon. Minister is aware that the Vidarbha region of Maharashtra is one of the most backward regions in the State; economically as well as industrially. There are some districts in the region which do not have even a single or medium industry. The position in regard to agriculture too is not very encouraging or impressive. The small-scale sector is the only hope for this backward region. But the SSI units are also very few in this region.

As per the figures given by your Ministry itself, in 1996, there were 14,346 SSI units in the whole of Vidarbha. In my opinion, the major hurdle for the SSI sector is the shortage of working capital. Banks do not give credit so easily. They always ask for collateral security.